

प्रश्नकाल

उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि जलशक्ति विभाग में पैरा फिटर, पैरा पंप आपरेटर, मल्टी पर्पज वर्करज के पांच हजार पद मंजूर किए हैं। इनमें से 25 सौ पदों को भर दिया गया है और बाकी पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान प्रश्नकाल में विधायक रीना कश्यप के सवाल के जवाब में उप मुख्यमंत्री ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार के समय में कुछ क्षेत्रों में 15-15 सौ पद भरे गए थे और इससे कई हलके ऐसे भी रहे, जहां कोई भर्ती नहीं हुई, इसे देखते हुए सरकार इस पूरी प्रक्रिया का युक्तिकरण कर रही है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पैरा वर्करज व जल रक्षकों को सरकार द्वारा निर्धारित पॉलिसी के तहत निर्धारित मानदेय के आधार पर रखा जाता है और पैरा वर्करज तथा जल रक्षकों पर कोई सेवा नियम लागू नहीं होते हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी श्रेणी के कर्मचारियों का मानदेय लंबित नहीं है, ठेकेदारों के माध्यम से हुई कुछ भर्तियों में मानदेय जारी होने में देरी का मामला हो सकता है। विधायक संजय रतन के मूल व आशीष बुटेल के अनुपूरक सवाल के जवाब में शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में बीपीएल चयन के लिए आय सीमा बढ़ाने का मामला केंद्र से उठाया जाएगा। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि इस मामले को लेकर केंद्र से आग्रह किया जाएगा।

वाकआउट

शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान आज सदन में एपीएमसी शिमला-किन्नौर की दुकानों के आवंटन में अनियमितताओं के आरोपों पर भारी हंगामा हुआ। प्रश्नकाल के दौरान उठे इस मामले में कृषि मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन में नारेबाजी की और पूरा विपक्ष नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चला गया। इससे पहले, प्रश्नकाल के दौरान भाजपा सदस्य सुधीर शर्मा और रणधीर शर्मा के मूल और बलबीर वर्मा के अनुपूरक सवाल के जवाब में कृषि मंत्री चन्द्र कुमार ने कहा कि एपीएमसी शिमला-किन्नौर द्वारा कुल 70 दुकानों का आवंटन किया गया है और इसमें कृषि विपणन बोर्ड द्वारा अधिसूचित आवंटन नीति 2021 में निर्देशित प्रक्रिया अपनाई गई।

भारतीय जनता पार्टी का काम है सिर्फ आरोप लगाना। फैक्ट्स और फिगर को वो चेक नहीं करेंगे। जो हमारी पॉलिसी है 2021 की, उसमें इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है किसानों के लिए जो है 25 परसेंट, और जो आढ़ती लोग हैं जो काम करते हैं उनके लिए 50 और सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, कॉपरेटिव सोसायटीज हैं या जो हमारे समूह हैं उनके लिए हम 10 परसेंट और एस सी, ओबीसी, एसटी, इनके लिए 15 परसेंट। समय के ऊपर अप्लाई किया उनकी सारी छानबीन की गई है।

आपदा-चर्चा

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता चंबा जिले में फंसे मणिमहेश यात्रियों को निकालने और आपदा प्रभावित तीनों जिलों चंबा, कांगड़ा और कुल्लू में मोबाइल नेटवर्क को बहाल करना है, ताकि फंसे लोगों से संपर्क किया जा सके। वे आज विधानसभा में नियम 62 के तहत विधायक नीरज नैय्यर, डॉ. हंस राज और डीएस ठाकुर द्वारा बीते तीन दिनों के दौरान आई प्राकृतिक आपदा से उत्पन्न हालातों को लेकर उठाए गए मामले पर हुई चर्चा के जवाब में बोल रहे थे। जगत सिंह नेगी ने कहा कि बीते 72 घंटों से प्रदेश के चंबा, कांगड़ा व कुल्लू जिले अतिवृष्टि से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं और कई स्थानों पर बाढ़ व भूस्खलन के चलते पठानकोट-चंबा राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध है जिससे सौ से अधिक वाहन फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मणिमहेश यात्रा मार्ग पर एक हजार से अधिक गाड़ियां फंसी हुई हैं। राजस्व मंत्री ने फंसे यात्रियों की संख्या को लेकर विपक्ष द्वारा सनसनी फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मणिमहेश स्थित डल झील में 150, गौरी कुंड में 100 से अधिक, धनछो में 500 से अधिक, हड़सर में 150 से अधिक लूना में एक हजार, कुगती में 20 और चौरासी मंदिर में 600 से अधिक लोग फंसे हुए हैं।

मौसम

राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम आमतौर पर साफ रहा जिससे पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश से लोगों को कुछ राहत मिली है। पिछले दिनों में हुई लगातार बारिश से प्रभावित सामान्य जनजीवन को पटरी पर लाने के प्रयास जारी हैं। चंबा जिले में भारी बारिश से हालात खराब हैं यहां 5 व्यक्तियों की मृत्यु का समाचार है। हमारे चम्बा जिला संवाददाता विकास ठाकुर ने बताया कि भू-स्खलन की चपेट में आने से एक मणिमहेश यात्री, बसोतन पंचायत के दो और मेहला ब्लॉक के दो लोगों मृत्यु हो गई है जबकि 7 व्यक्तियों के घायल होने की सूचना है। उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने बताया कि मणिमहेश यात्रा में अभी भी सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं जिन्हें हेलीटैक्सी के माध्यम से रेस्क्यू किया जा रहा है। चंबा में सड़क व संचार सेवाएं पूरी तरह बाधित हैं जिन्हें बहाल करने के प्रयास जारी हैं। कुल्लू जिले में राष्ट्रीय उच्च मार्ग सहित ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों और पुलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। उपायुक्त कुल्लू तोरुल एस.रवीश ने जिले के सभी पेट्रोल पम्पों को आपातकालीन सेवाओं के लिए आगामी आदेशों तक न्यूनतम रिजर्व स्टॉक बनाए रखना अनिवार्य कर दिया है। मौसम विज्ञान केन्द्र शिमला ने आगामी एक सितंबर तक राज्य में कुछ स्थानों में भारी बारिश की चेतावनी दी है।
